करेंट अफेयर्स[27 अगस्त] 2022

जस्टिस यूयू ललित बने देश के 49वें चीफ जस्टिस

पाठ्यक्रम -सामान्य अध्ययन पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था)

खबरों में क्यों?

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनकी नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर करने के बाद बुधवार को भारत का 49वां प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) नियुक्त किया गया।

न्यायमूर्ति एनवी रमना के प्रधान न्यायाधीश का पद छोड़ने के एक दिन बाद न्यायमूर्ति ललित 27 अगस्त को कार्यभार संभालेंगे। न्यायमूर्ति ललित का संक्षिप्त कार्यकाल होगा क्योंकि वह तीन महीने से कुछ कम समय तक प्रधान न्यायाधीश का पदभार संभालने के बाद आठ नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे।

न्यायमूर्ति ललित दूसरे प्रधान न्यायाधीश होंगे जिन्हें बार से सीधे शीर्ष अदालत की पीठ में पदोन्नत किया गया है।

न्यायमूर्ति एस एम सीकरी मार्च 1964 में सीधे शीर्ष अदालत की पीठ में पदोन्नत होने वाले पहले वकील थे और जनवरी 1971 में 13 वें सीजेआई बने।

सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के प्रावधान

- उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ और मुहर के अधीन वारंट द्वारा उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के पश्चात् की जाएगी जो राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे और 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है।
- **सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में**, न्यायालय ने कहा कि सीजेआई का दृष्टिकोण राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, न्यायालय ने यह भी माना कि राष्ट्रपति को सलाह देते समय सीजेआई से दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने की उम्मीद की जाती है।
    - सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का एकमात्र अधिकार है। सीजेआई और राष्ट्रपति के बीच विचारों के टकराव के मामले में, सीजेआई द्वारा व्यक्त किए गए विचार का प्राथमिक होगा।

जुलाई 1998 में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर न्यायालय की राय मांगी।

ग्यारहवें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण राय से संबंधित 1993 के मामले में निर्धारित भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया पर कुछ संदेहों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था।

क्रूक्स इस प्रकार है:

- न्यायिक नियुक्तियों में, राष्ट्रपति के लिए सीजेआई की राय को ध्यान में रखना अनिवार्य है।
- सीजेआई की राय सरकार के लिए बाध्यकारी है। सीजेआई की राय सुप्रीम कोर्ट के कम से कम चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के साथ उचित परामर्श के बाद बनाई जानी चाहिए।
- यहां तक कि अगर दो न्यायाधीश प्रतिकूल राय देते हैं, तो उन्हें सरकार को सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए पात्रता मानदंड

भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 [3] में कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए, व्यक्ति को निम्नलिखित मानदंडों में फिट होना चाहिए:

- वह **भारत का नागरिक** है और
- कम से कम **पांच वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या** उत्तराधिकार में दो या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों के न्यायाधीश रहे हैं; नहीं तो
- कम से कम **दस वर्षों तक एक उच्च न्यायालय या** उत्तराधिकार में दो या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों के वकील रहे हैं; नहीं तो
- **राष्ट्रपति की राय** में, एक प्रतिष्ठित न्यायविद है।

भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए नियमों का एक सेट भी प्रदान करता है। **अनुच्छेद 124 (4)** में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के उन निष्कासन नियमों का उल्लेख किया गया है।

एक बार नियुक्त होने के बाद, न्यायाधीश पूरे **65 वर्षों** तक पद धारण कर सकते हैं। उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान **साबित कदाचार या अक्षमता** के अलावा हटाया नहीं जा सकता है.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण

पाठ्यक्रम -सामान्य अध्ययन पेपर III

खबरों में क्यों?

2021-22 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने वर्ष में दो पीएसबी के निजीकरण को शुरू करने के अपने इरादे की घोषणा की और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश की नीति को मंजूरी दी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्या हैं?

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) वे बैंक हैं जिनके पास 50% से अधिक स्वामित्व है

निजी क्षेत्र के बैंक -

निजी क्षेत्र के बैंक वे बैंक हैं जहां **निजी व्यक्तियों या निजी कंपनियों के पास बैंक की इक्विटी का एक बड़ा हिस्सा है।**

पुलित्जर पुरस्कार, 2022

बांग्लादेश में जन्मी चित्रकार और कहानीकार **फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है**। वर्तमान में, वह एक अमेरिकी ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम कर रही है। फहमीदा को न्यूयॉर्क में अपनी विजेता टीम के सदस्यों एंथनी डेल कोल, जोश एडम्स और इनसाइडर्स वॉल्ट हिक्की के साथ "हाउ आई एस्केप्ड ए चाइनीज इंटर्नमेंट कैंप" नामक एक सचित्र रिपोर्ट के लिए सम्मानित किया जाता है।

पुलित्जर पुरस्कार क्या है?

- एक पुरस्कार जो समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, संगीत रचना, ऑनलाइन पत्रकारिता और साहित्य में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है।
- यह पुरस्कार वर्ष 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत में लिखे गए प्रावधानों द्वारा स्थापित किया गया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय इस पुरस्कार का संचालन करता है।
- ये पुरस्कार सालाना 21 श्रेणियों में दिए जा रहे हैं। 20 श्रेणियों में, विजेताओं को 15,000 अमरीकी डालर और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। पुरस्कार की लोक सेवा श्रेणी में विजेता को स्वर्ण पदक मिलता है।